

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक 09 अक्टूबर, 2007

विषय:-पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानों के घेरबाड़ की नई योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-262/1-1(102)/2007-08, दिनांक 10 अगस्त, 2007 तथा पत्रांक-405/1-1(102)/2007-08 दिनांक-12 सितम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2007-08 में राज्य सैक्टर की योजना के रूप में सम्मिलित "पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानों के घेरबाड़" की नई योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष में उप मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में प्राविधानित रु०-92.00 लाख (रुपये बयानब्वे लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- योजना का क्रियान्वयन शासन के पत्र संख्या-812/XVI/07/7(56)/2007, दिनांक- 09 अगस्त, 2007 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं अन्य सुसंगत विवरणों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-599/XXVII (1)/2007, दिनांक-12 जुलाई, 2007 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रक्रिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्ठादन नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 आय व्ययक सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- 5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 6- व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- 7- व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।



8- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति श्रेणी के कास्तकारों/उद्यानपतियों को ही नियमानुसार राज सहायता प्रदान की जायेगी।

9- योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में अनुसूचित जाति के महिला कास्तकारों को भी नियमानुसार अधिमान दिया जायेगा, साथ ही इस श्रेणी के लघु/सीमान्त कास्तकारों पर विशेष ध्यान लाभार्थियों के चयन के समय दिया जायेगा।

10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत-119-बागवानी और सब्जियों की फसलें-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-16-उद्यानों की घेरबाड़ योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-173(P)/वित्त अनु0-4/2007, दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव।

संख्या-1067/XVI/07/7(52)/07/तददिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- वित्त अनुभाग-4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
- ✓ 5- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 6- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अहमद अली

(अहमद अली)

अनु सचिव।